बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 239 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 10 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

एबीवीपी के 78 वें स्थापना दिवस पर बोलीं रेखा गुप्ता, राष्ट्र सर्वोपरि है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने संगठन के कार्यकर्ताओं और छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कर कहा, कुछ ऋण जीवन भर चुकाए नहीं जाते, केवल अपने कर्मों से निभाए जाते है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऋण मेरे जीवन पर ऐसा ही है। एबीवीपी ने मुझे राष्ट्रसेवा के संस्कार दिए, जीवन का उद्देश्य दिया। यहीं सीखा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कार्यकर्ता का सबसे बड़ा परिचय उसके पद से नहीं, उसके समर्पण से होता है।

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु जनजातियों की सर्वेक्षण

जनगणना एवं न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की माँग को लेकर भारतीय जन सम्मान पार्टी का वक्तव्य

नई दिल्ली। भारतीय जन सम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि देश के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु जनजाति समुदाय लंबे समय से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इन समुदायों की वास्तविक जनसंख्या, सामाजिक स्थिति तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं के समुचित आँकड़ों का अभाव नीति निर्माण में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जन सम्मान पार्टी भारत सरकार से आग्रह करती है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु जनजातियों का देशव्यापी वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं समुचित जनगणना कराई जाए, ताकि इन समुदायों की वास्तविक स्थिति, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का सही आकलन हो सके। विश्वसनीय आँकड़ों के आधार पर ही इनके उत्थान के लिए प्रभावी योजनाएँ और नीतियाँ बनाई जा सकती है। रविन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि इन समुदायों को संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर और सामाजिक न्याय का लाभ व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने माँग की कि सर्वेक्षण एवं जनगणना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर, लागू संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप, इनके लिए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व तथा आवश्यक संरक्षणात्मक उपायों पर गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जन सम्मान पार्टी का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास, सम्मान और समान अवसर पहुँचाना है। पार्टी का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध हों। भारतीय जन सम्मान पार्टी केंद्र एवं राय सरकारों से आग्रह करती है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए तथा उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएँ।

अवैध कब्जों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; अधिकारियों की मिलीभगत पर जताई नाराजगी, पूछा- क्या कार्रवाई हुई?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली- लखनऊ में हुए हालिया अग्निकांड की घटनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निकायों को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में अवैध कब्जों को लेकर भी नाराजगी जताई और पूछा कि अवैध कब्जों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

अदालत ने नगर निकायों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जमीन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने अवैध कब्जों के मामलों में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत पर भी कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने घटना के बाद अधिकारियों द्वारा इज्जत बचाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की भी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि घटनाओं के बाद सिर्फ बिल्डरों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि घटना वाले क्षेत्र के प्रभारी अधिकारियों को छोड़ दिया जा रहा है। कोर्ट ने रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी। दिल्ली के मालवीय नगर में बीती 3 जून को एक होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं लखनऊ में बीती 22 जून को एक व्यवसायिक परिसर में लगी आग में झुलसकर 15 लोगों की मौत हो गई थी।अदालत ने दिल्ली नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे नगर निकाय के आचरण से चिंतित हैं। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की पीठ ने अवैध कब्जों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मालवीय नगर की घटना, लखनऊ में लगी आग और साकेत में इमारत गिरने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि अधिकारी कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अदालत ने ये भी पूछा कि मालवीय नगर की घटना के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लाजपत नगर, साकेत और सरोजनी नगर जैसे इलाकों का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है और इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस विशेषज्ञ समिति में आईआईटी दिल्ली के सिविल विभाग के दो वरिष्ठ प्रोफेसर, आईआईटी के दो ड्राफ्ट्समैन और एमसीडी के अधिकारी और कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी भी शामिल रहेंगे। विशेषज्ञ समिति अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अदालत ने बीती 20 मई को सुरक्षा अधिकारियों को सुरक्षा मानदंड पर निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर भी संज्ञान लिया, जिनमें बताया गया कि गुरुग्राम की 93 प्रतिशत इमारतें अग्नि सुरक्षा ऑडिट में फेल रही हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों को 20 मई को निर्देश दिए गए थे कि क्या करना है। लेकिन आदेश के बावजूद एनसीआर में अग्निकांड हुए। अदालत ने पूछा कि उनके आदेश के बाद अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? अदालत ने कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

यूजीसी- नेट विवाद को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए को भंग करने की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस ने यूजीसी- नेट की परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को भंग किया जाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि शिक्षा मंत्रालय कमजोर है और एनटीए को जानबूझकर अक्षम एवं निष्क्रिय बना दिया गया है जिसके कारण परीक्षा का प्रारूप बदलने के बावजूद प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताएं जारी हैं। मई 2026 में नीट-यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के कुछ ही दिनों बाद मंत्री प्रधान ने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें यह निहित संदेश था कि पेन और पेपर आधारित परीक्षा के विपरीत, सीबीटी का पेपर लीक नहीं हो सकता। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि मई , 2026 में नीट-यूजी परीक्षा पत्र लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के रूप में आयोजित की जाएगी। उनके अनुसार, इससे यह संदेश दिया गया कि सीबीटी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक नहीं हो सकता। रमेश ने दावा किया कि अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इस वर्ष का यूजीसी-नेट समाजशास्त्र परीक्षा का प्रश्नपत्र भी कथित रूप से लीक हुआ है जबकि यह परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इससे पहले यूजीसी-नेट अंग्रेजी परीक्षा में प्रश्नों को पुराने प्रश्नपत्रों से बिना किसी बदलाव के उठाया गया था। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि परीक्षा का प्रारूप चाहे जो भी हो, प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताएं जारी हैं। उन्होंने मंत्री प्रधान के इस्तीफे और एनटीए को भंग किए जाने की मांग दोहराई।

102 नहीं, 82 लीटर हो पेट्रोल- केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा- सरकार तेल कंपनियों को दिला रही अवैध मुनाफा

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल कंपनियों को अवैध मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कचे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद देश में ईंधन के दाम नहीं घटाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने मांग की कि सरकार को आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल की कीमत तुरंत 102 रुपये से घटाकर 82 रुपये प्रति लीटर करनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम घटे, भारत में क्यों नहीं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कचे तेल की प्रति बैरल कीमत में काफी कमी आई है। इसके बावजूद भारत में इस साल मई महीने से पेट्रोल की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर पर ही टिकी हुई है। मेरी मांग है कि पेट्रोल के दाम घटाकर 82 रुपये प्रति लीटर किए जाएं और इसी अनुपात में डीजल की कीमतों में भी कटौती की जाए।

ईंधन सस्ता होने से कम होगी महंगाई

आप संयोजक ने तर्क दिया कि अगर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाती हैं, तो इसका सीधा असर माल ढुलाई और अन्य सेवाओं पर पड़ेगा, जिससे देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

जनता की जेब काटकर अवैध मुनाफा कमा रही तेल कंपनियां

उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल 2014 से लेकर अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कचे तेल की कीमतों में कम से कम छह बार बड़ी गिरावट आई है, लेकिन सरकार ने देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाए। सरकार उन वर्षों के दौरान कमाए गए इस बंपर मुनाफे का क्या कर रही है? कंपनियों को जनता की जेब काटकर इस तरह अवैध मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जो कि मौजूदा समय में ऊंचे दामों के जरिए हो रहा है।

ई20 पेट्रोल : माइलेज पर मामूली असर, इंजन पर नहीं-गडकरी

नई दिल्ली। वाहनों में पेट्रोल के साथ यादा इथेनॉल मिलाने को लेकर बहस जारी है। इस बीच, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इसलिए जैसे-जैसे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है, वैसे-वैसे गाड़ी का औसत माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यादातर मामलों में इसका असर बहुत कम होगा। गडकरी ने यह बात इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ई20 पेट्रोल से वाहनों के खराब होने की जो बातें सामने आ रही हैं, उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक, यह एक सुनियोजित दुष्प्रचार है। गडकरी ने कहा कि ई20 मिश्रण (20 फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल) को पूरे देश में लागू करने से पहले पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और वाहन बनाने वाली कंपनियों ने कई तरह के परीक्षण किए थे। सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया गया। पुराने वाहनों के कुछ छोटे पुर्जों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए वाहन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि सर्विस के दौरान वे ऐसे पुर्जों को बदल दें। गडकरी ने कहा, मुझे एक भी ऐसी गाड़ी दिखाइए जो ई20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो। सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे एक सुनियोजित दुष्प्रचार का हिस्सा हैं।

माइलेज को लेकर गडकरी ने क्या कहा?

माइलेज के बारे में गडकरी ने कहा, देखिए, दो बातें हैं। पहली, इथेनॉल और पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता में अंतर है, यह सच है। लेकिन माइलेज इस बात पर भी निर्भर करता है कि वाहन किन परिस्थितियों में चलाया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक के कारण गाड़ियां अक्सर कम गियर में चलती हैं। उन्होंने एआरएआई की की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि खास तौर पर फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में माइलेज की कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम फ्लेक्स-फ्यूल इंजन तकनीक को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, तो बार-बार ब्रेक लगाना पड़ता है। लाल बत्ती आने से पहले गाड़ी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यादा नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, तो माइलेज में कुछ अंतर दिखाई दे सकता है।

इंजन में खराबी के दावों पर क्या कहा?

इंजन खराब होने के दावों पर नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने कुछ मामलों की जांच करने के लिए कंपनियों से कहा था। जांच में पता चला कि वहां मिलावटी ईंधन जिम्मेदार था, ई20 पेट्रोल नहीं। गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल इंजन बनाने के दौरान कई नई बातें सीखने को मिलीं और इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जों में भी सुधार किया गया है। उन्होंने कहा, पुरानी गाड़ियों में सर्विस के दौरान इस्तेमाल होने वाले कुछ वॉशर पहले धातु के होते थे। अब वे रबर के बनाए जा रहे हैं। हमने वाहन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सर्विस के समय ये वॉशर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदल दिए जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरी जानकारी में ई20 पेट्रोल की वजह से कोई गाड़ी बंद नहीं हुई है। प्रदर्शन की बात करें तो इथेनॉल बेहतर साबित हुआ है। इसमें इंजन की नॉकिंग कम होती है और इसका ऑक्टेन नंबर भी यादा है। मैं वर्ष 2004 से इथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की बात करता रहा हूं।

नए मॉडल बाजार में लाने की तैयारी में कंपनियां?

उन्होंने कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल इंजन तकनीक आने के साथ करीब एक दर्जन कंपनियां अपने नए मॉडल बाजार में लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा किर्लोस्कर और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ब्राजील में वर्ष 1970 से 27 फीसदी इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहां होंडा और हुंडई की फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां बिना किसी परेशानी के चल रही हैं। गडकरी ने कहा, हमारा उद्देश्य लोगों को विकल्प देना है। अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग ईंधन मिश्रण उपलब्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि इथेनॉल की कीमत लगभग 75 रुपये प्रति लीटर है। उन्होंने कहा, फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड वाहन यादा ईंधन बचाते हैं, क्योंकि इनमें लगी इलेक्ट्रिक प्रणाली ऊर्जा को बैटरी में जमा कर देता है। गडकरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट ने यह दिखा दिया है कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हरसंभव विकल्प तलाशना जरूरी है। उन्होंने बताया, कर्नाटक में अशोक लेलैंड ने कर्नाटक राय परिवहन निगम के साथ मिलकर 15 फीसदी मेथेनॉल और डीजल के मिश्रण पर 25 बसें तीन महीने तक चलाईं। इसके बाद प्रमाणित किया गया कि कोई समस्या नहीं आई।

फिर अशोक लेलैंड ने ऐसा विशेष मेथेनॉल इंजन विकसित किया, जिससे ट्रक और बसें पूरी तरह मेथेनॉल पर चल सकें। उन्होंने आगे कहा, अभी असम पेट्रो-केमिकल्स रोज 700 टन मेथेनॉल बनाती है। इसकी कीमत लगभग 20 से 22 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत करीब 110 रुपये प्रति लीटर है। इससे काफी खर्च बच सकता है। उन्होंने कहा कि इस ईंधन से प्रदूषण भी बहुत कम होता है।

पूर्वोत्तर भारत में ट्रक और बसों के लिए मेथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह समुद्री इंजनों के लिए भी बहुत अछा ईंधन है। ब्रह्मपुत्र नदी में जल परिवहन और बांग्लादेश जाने वाली नौकाओं में मेथेनॉल से चलने वाले इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

सम्पादकीय...

आत्मनिर्भता

आज जब आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की बात होती है तो इसकी नींव भारत के गाँवों में ही पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहबाद की ग्राम पंचायत किरा ने इस दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए न केवल स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाया है, बल्कि इसमें आर्थिक स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों के सतत् विकास एवं संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रम में जिले में स्थित गौशाला के 769 गौवंशों से दैनिक निकलने वाले लगभग 3,845 किलोग्राम गोबर का सदुपयोग किये जाने के उद्देश्य से यहाँ पर 85 घन मीटर क्षमता वाला बायोगैस प्लांट स्थापित कर संचालित किया गया है, जिससे ग्रामीणों की जीवनशैली में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बायोगैस प्लांट की स्थापनाः गाँव की पंचायत की बैठक में जब ग्राम प्रधान के द्वारा ऊर्जा संकट, मवेशियों से निकलने वाले गोबर का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और आय सृजन के विषय पर चर्चा हुई, तब यह निर्णय लिया गया कि गांव में एक बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाए। इसी क्रम में यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अन्तर्गत प्राप्त रू0 40.00 लाख की धनराशि से 85 घन मीटर की क्षमता के साथ बायो गैस प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट के संचालन हेतु प्रतिदिन 2125 किलोग्राम गोबरकी आवश्यकता होती है, जो ग्रामवासियों के सहयोग से जुटाया जाता है। यह पहल ग्रामीणों को न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाती है, बल्कि गोबर की उपयोगिता को भी दर्शाती है। ऊर्जा उत्पादन और उसका सदुपयोगः इस प्लांट में प्रतिदिन 51 किलोग्राम बायोगैस का उत्पादन हो रहा है, जिसका इस्तेमाल करके 15 केवीए जनरेटर से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। अब तक इस प्रणाली से 25200 यूनिट विद्युत उत्पन्न की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत ?2.52 लाख है। इस बायोगैस से बनी बिजली के उपयोग से न केवल ऊर्जा की बचत हुई है, बल्कि बिजली की निर्भरता कम होने से आर्थिक बचत भी हुई है। इस बायोगैस से चारा मशीनचलाने के लिए, गांव की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था के लिए, गौशाला के सबमर्सिबल पंपों के संचालन हेतु तथा गौशाला के केयरटेकरों के लिए रसोई गैस के रूप में उपयोग की जा रही है। स्लरी से आय और ओएसआर में वृद्धि हो रही हैः बायोगैस प्लांट में निकली स्लरी अत्यंत पोषक जैविक खाद होती है। ग्राम पंचायत ने इस स्लरी को उचित मूल्य पर किसानों को बेचकर ?53,800.00की आय अर्जित की है, जिसे पंचायत के ओन सोर्स रेवेन्यू खाते में जमा कराया गया है। यह आय पंचायत के विकास कार्यों में पुनः निवेश की जा रही है, जिससे एक सतत आर्थिक चक्र की स्थापना हो रही है। ग्राम पंचायत किरा ने बायोगैस प्लांट की सफलता से प्रेरित हो कर कोल्ड प्रेस ऑयल स्पेलर मशीन की स्थापना की योजना बनाई है, जो अब प्रगति पर है। इसके माध्यम से गांव में उगाई गई सरसों से शुद्ध तेल का निष्कर्षण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की भूमिकाः नेतृत्व, जागरूकता और भागीदारीः इस पूरे परियोजना की सफलता का श्रेय ग्राम पंचायत के दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी को जाता है। पंचायत ने न केवल तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया, बल्कि ग्रामीणों को जागरूक कर उन्हें इस परिवर्तन का भागीदार भी बनाया। नियमित जनसभाओं, गोष्ठियों और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से लोगों को बायोगैस के उपयोग, स्लरी के लाभ, स्वच्छता के महत्व और वैकल्पिक ऊर्जा के महत्व के बारे में बताया गया। पर्यावरणीय लाभः हरित क्रांति की ओरः बायोगैस प्लांट ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ठोस कदम उठाया है। इसके कई लाभ हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कमी आ रही है। गोबर से निकलने वाला मीथेन गैस वातावरण में नहीं जा रहा है, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव घटा है। खुले में गोबर फैलाने की प्रवृत्ति में कमी आई है, जिससे स्वच्छता में सुधार हुआ है। स्लरी का उपयोग रासायनिक खाद की जगह करने से जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। डीजल जनरेटर की जगह बायोगैस जनरेटर का उपयोग हो रहा है, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है। इस परियोजना का एक अन्य सकारात्मक पहलू यह है कि इससे यहाँ पर रोज़गार भी मिल रहा है। पहले गौशाला में खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का प्रयोग होता था, जिससे धुएं की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ थीं। अब केयरटेकर महिलाओं के लिए बायोगैस से खाना बनाना आसान और स्वास्थ्यवर्धक हो गया है। इसके साथ ही गांव में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं गोबर एकत्र करने, मशीन संचालन, स्लरी प्रबंधन और तेल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में गाँव के लोगों को रोजगार भी मिला है। ग्राम पंचायत किरा की यह कहानी सिद्ध करती है कि यदि इच्छाशक्ति दूरदृष्टि और सामूहिक प्रयास हो, तो कोई भी गांव आत्मनिर्भर, पर्यावरण के प्रति जागरूक और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकता है। बायोगैस प्लांट ने न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार और आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। ग्राम पंचायत किरा एक मॉडल के रूप में उभरकर सामने आई है, जो अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना है।

मोदी का हिन्द प्रशांत मिशन

भारत-इंडोनेशिया संबंध 2 हजार वर्षों से भी गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक संबंधों पर आधारित हैं। दोनों देश महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी भी हैं, जिनकी समुद्री सीमाएं भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच लगभग 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित हैं। इंडोनेशिया की आजादी में भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इंडोनेशिया पहले नीदरलैंड का उपनिवेश था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने उस पर कब्जा कर लिया था। 1945 में जापान की हार के बाद इंडोनेशिया ने स्वयं को आजाद देश घोषित कर दिया था लेकिन नीदरलैंड और अन्य देश मानने को तैयार नहीं थे। जब इंडोनेशिया और डच सेना में भीषण लड़ाई शुरू हो गई तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जो शुरूआती जीवन में एक पायलट थे, को इंडोनेशिया के शीर्ष नेतृत्व को बचाकर भारत लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब बीजू पटनायक भारतीय वायुसेना का डेकोटा विमान लेकर इंडोनेशिया पहुंच गए थे और वे ही इंडोनेशिया के नेता सुकर्णो और सुल्तान शहरयार को बचाकर दिल्ली ले आए थे। इंडोनेशिया को 1949 में आजादी ?मिली। दोनों देशों के संबंधों का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सुकर्णो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों में 20 अहम समझौते हुए। इन समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण डील इंडोनेशिया द्वारा भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने की रही लेकिन समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों देशों का रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने का फैसला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्द प्रशांत पर अपने विजन के अनुरूप कूटनीतिक दांव खेल दिया है। भले ही यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक डील दिखाई दे लेकिन वास्तव में यह हिन्द महासागर में भारत का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जकार्ता, ऑकलैंड और मेलबॉर्न यात्रा का उद्देश्य ही हिन्द प्रशांत समुद्री इलाके के नक्शे को फिर से बनाना है। इससे वहां रहने वाली ताकतों को स्वायत्तता वापिस मिलेगी और यह इलाके की कहानी को सबका साथ और सबका विकास पर केन्द्रित करेगा। जिस तरह से चीन हिन्द प्रशांत में अपना दबदबा कायम कर रहा है और अमेरिका शोषण करने वाली या ब्लैकमेलिंग करने वाली मनमानी कर रहा है, उससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। भारत सहयोग की एक नई थ्योरी की कल्पना करता है जो चीन और अमेरिका द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर न हो, बल्कि यहां रहने वाले देशों द्वारा खुद बनाई गई हो। साबांग बंदरगाह के जरिये भारत सीधे चीन की सबसे दुखती रग यानि मलक्का स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बढ़ाएगा। सिर्फ यही नहीं इंडोनेशिया के पास ऐसे कई समुद्री चोक प्वांइट्स हैं जहां से दुनिया के कई बड़े देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है। साबांग बंदरगाह भारत के पोर्ट ब्लेयर से महज कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच बढ़ते गहरे तालमेल के बाद भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों पर अपनी पकड़ को अभूतपूर्व रूप से मजबूत, कर लेगा। भारत और इंडोनेशिया की यह जुगलबंदी इन समुद्री रास्तों के मुहाने पर एक ऐसी मजबूत दीवार की तरह काम करेगी, जिसे लांघ पाना किसी भी दुश्मन नौसेना के लिए मुमकिन नहीं होगा। इस डील का सबसे बड़ा एंगल ये है कि दोनों देश मिलकर पूरे 'इंडो-पैसिफिक' क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही का 'रियल-टाइम डेटा' यानी पल-पल की खुफिया जानकारी आपस में साझा करेंगे। मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे व्यस्त और रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जो हिन्द महासागर को दक्षिणी चीन से जोड़ता है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा अकेले इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। हर साल इस रास्ते से 90,000 से अधिक मालवाहक और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। आर्थिक मूल्य के लिहाज से देखें तो हर साल खरबों डॉलर का सामान इसी रास्ते से दुनिया भर में सप्लाई होता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये रास्ता और भी अहम है। दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कुल कच्चे तेल के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से जाता है। हर रोज इस संकरे रास्ते से लगभग 16 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। सबसे बड़ी बात ये है कि चीन अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल इसी मलक्का स्ट्रेट के जरिए मंगाता है। साबांग पोर्ट पर भारत की पहुंच होने के बाद, भारतीय नौसेना चीनी नौसेना के युद्धपोतों और उसके तेल टैंकरों जैसी हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर गिद्ध जैसी नजर रख सकती है। अगर कभी युद्ध या भारी तनाव की स्थिति बनी तो भारत के पास इस चोक प्वाइंट को पूरी तरह ब्लॉक करने की क्षमता होगी जिससे चीन तड़प उठेगा। इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल की खरीद भी चीन को परेशान करने वाली है। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इंडोनेशिया के क्रिटिकल ?मिनरल्स क्षेत्र में चीन का भारी निवेश और दबदबा है और इस पर डील चीन को एक तरह से कूटनीतिक जवाब है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इंडोनेशिया की संसद में खड़े होकर चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की नीतियां विस्तारवादी नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में बहुत मजबूती आई है। दोनों देशों का लक्ष्य तकनीकी, सांस्कृतिक और बहुपक्षीय कोशिशों के माध्यम से सहयोग बढ़ाना और हिन्द प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को मजबूत करना है।

पाकिस्तान की अल्पसंख्यक नीति जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग

पाकिस्तान वर्षों से स्वयं को अल्पसंख्यकों के हितैषी और धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर बताने का प्रयास करता रहा है। विशेषकर जब सिख श्रद्धालुओं की यात्रा, करतारपुर कॉरिडोर या अन्य धार्मिक आयोजनों की बात आती है तब वहां की सरकार और प्रशासन स्वयं को सहिष्णु और उदार राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते लेकिन प्रश्न यह है कि यदि वास्तव में पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकारों का इतना बड़ा संरक्षक है तो उसके अपने देश में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की दुर्दशा क्यों दिखाई देती है? देश के विभाजन के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान में हजारों मंदिर, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थल या तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए, या उन पर अवैध कब्जे कर लिए गए अथवा उन्हें अन्य उपयोगों में परिवर्तित कर दिया गया। हाल ही में फैसलाबाद (पूर्व नाम फासलाबाद) स्थित लगभग 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब को ध्वस्त किए जाने की घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के उन दावों की पोल खोल दी है जिनमें वह धार्मिक सहिष्णुता का ढोल पीटता है। इसी प्रकार कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हटाकर वहां स्कूल या अन्य संस्थान चलाए जाने की खबरें भी सामने आती रही हैं। यह केवल भवनों का प्रश्न नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रश्न है। विडंबना यह है कि एक ओर पाकिस्तान भारतीय सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को श्रद्धा और सम्मान का संदेश देते हुए अपने यहां आने का निमंत्रण देता है, वहीं दूसरी ओर उसके अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक भय, असुरक्षा और भेदभाव का सामना करने को विवश हैं। धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण, जबरन धर्म परिवर्तन, अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के अपहरण और न्याय पाने में आने वाली कठिनाइयों जैसे मुद्दे समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठते रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की कथनी और करनी के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि पाकिस्तान वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के सम्मान में विश्वास रखता है तो उसे केवल प्रचार और प्रतीकात्मक आयोजनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे अपने देश में स्थित सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, अवैध कब्जों को हटाना होगा, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी होगी। यह केवल भारत या सिख समुदाय का विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा वैश्विक प्रश्न है। श्री अकाल तख्त साहिब की गरिमा कायम रखना बेहद जरूरी श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना छठे गुरु हरिगोबिन्द साहिब जी ने की थी तभी से यह संसार भर के सिखों के लिए सर्वोच्च धार्मिक स्थल है और यहां से जारी फरमान को हर सिख मानने के लिए बाध्य रहता है। महाराजा रणजीत सिंह जैसे शक्तिशाली शासक ने भी अकाल तख्त के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और धार्मिक अनुशासन के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सिख समाज के एक वर्ग में यह चिंता लगातार सुनाई देती है कि श्री अकाल तख्त साहिब के कुछ निर्णयों को लेकर निष्पक्षता पर प्रश्न उठ रहे हैं। यदि समाज के किसी वर्ग को यह महसूस होने लगे कि अलग-अलग व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं, तो इससे संस्था के प्रति विश्वास प्रभावित हो सकता है। चाहे यह धारणा सही हो या गलत, उसका उत्पन्न होना ही गंभीर आत्ममंथन की मांग करता है।

पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए?

अगर कोई और यह बात कहता तो तत्काल उसे पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाता। उसे एंटी- नेशनल करार दिया जाता। सोशल मीडिया की तोपों के द्वारा उसके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जाता, पर यहां तो संघ के वरिष्ठ अधिकारी दत्तात्रय होसबाले कह रहे थे कि पाकिस्तान की पुलवामा जैसी हरकतों का जवाब देते हुए भी हमें दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हमें सदा बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान की तरफ पहल को एक मिसाल कहा कि बार-बार उत्तेजना के बावजूद उन्होंने संवाद जारी रखा। दत्तात्रय होसबाले भूल गए कि अटल जी की लाहौर यात्रा के दौरान ही पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, फिर भी होसबाले का सुझाव असमान्य है क्योंकि वह संघ के बड़े अधिकारी हैं और वह लोग अचानक ऐसे सुझाव नहीं देते। हर बात को सोच-समझ कर, नाप-तोल कर कहा जाता है। राम मंदिर में गबन पर भी होसबाले ने ही संघ की प्रतिक्रिया व्यक्त की है, पर काफी दिनों के बाद, सोच-समझ कर, नाप-तोल कर। इस समय अचानक होसबाले ने यह गुब्बारा क्यों उड़ा दिया? देश तो प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों से बंधा है कि 'टैरर एंड टॉक्स' आतंक और बातचीत, इकट्ठे नहीं चल सकते। हैरानी है कि होसबाले ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान पुलवामा जैसे 'पिन प्रिक्स' देता रहे तो हमें स्थिति के मुताबिक जवाब देना चाहिए। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और संघ के वरिष्ठ अधिकारी इसे मामूली सुई की चुभन कह रहे हैं ! वह पहलगाम को भूल गए। बाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी उनकी बात का समर्थन कर दिया। क्या सरकार की तरफ से लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए यह ट्रायल बलून उड़ाया गया? क्या कोई खिचड़ी पक रही है? यह भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में होसबाले के बयान का स्वागत किया गया है और इसे 'सकारात्मक कदम' कहा है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता का कहना था कि उन्हें आशा है कि विवेक की जीत होगी। जो आतंकवाद का प्रायोजक है वह ही पीड़ित को विवेक की सलाह दे रहा है। संघ के लोग कह रहे हैं कि होसबाले का बयान 'पाकिस्तान के लोगों के लिए है। पाकिस्तान की सरकार के लिए नहीं'। यह बेमतलब की बात है। पाकिस्तान की अवाम मायने नहीं रखती। वास्तव में तो सरकार भी मायने नहीं रखती, मायने केवल वहां की ताकतवर सेना रखती है और कोई संकेत नहीं कि भारत प्रति उनकी दुश्मनी कम हुई है। भारत और पाकिस्तान पर अमेरिका एक्सपर्ट स्टीफन कोहेन ने कहा है किपाकिस्तान की विदेश नीति वास्तव में उनकी सेना की विदेश नीति बन गई है,- पर वह एक और दिलचस्प बात कहते हैं किपाकिस्तान की सेना आतंकवाद और कश्मीरी अलगाववादियों को समर्थन देते हुए भी नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति पहुंच जाए कि भारत के साथ सीधा टकराव हो- इसीलिए होसबाले की भाषा में, 'पिन प्रिक्स' देते रहते हैं। पुलवामा, उरी, पठानकोट, पहलगाम, यह सब सीमित उत्तेजना है। कारगिल जैसा बड़ा दुस्साहस दोबारा नहीं किया गया। इस समय होसबाले ने यह धमाका क्यों किया ? क्या देश को 'आतंक और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकते' की नीति पर पुनर्विचार के लिए तैयार किया जा रहा है? जो पहल खुद अभी सरकार नहीं उठाना चाहती, वह संघ की मार्फत उठाई जा रही है? यह भी दिलचस्प है कि होसबाले का यह सुझाव उनकी अमेरिका यात्रा के तत्काल बाद आया है। क्या वहां से कोई दबाव है? क्या इस प्रयास के पीछे अमेरिका का हाथ है? ट्रम्प प्रशासन का पाकिस्तान के प्रति रवैया बहुत ममता भरा है। ट्रम्प मुनीर की तारीफ करते नहीं थकते और उपराष्ट्रपति वैंस ने हाल में कहा है कि 'वी लव पाकिस्तान'। जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को अपनी एबटाबाद छावनी में छिपाए रखा था, अगर उनके लिए वैंस का लव उमड़ रहा है तो उन्हें मुबारक,पर हमारे लिए तो समस्या है

अभी तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री समेत, सबने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है और सबके हाथ झुलस गए। यही कारण है देश में पाकिस्तान के साथ संवाद शुरू करने के प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं रही। वरिष्ठ वकील और विपक्षी नेता कपिल सिब्बल ने होसबाले के सुझाव को वाहियात कहा है। उनका कटाक्ष है कि अगर वह यह बात कहते तो उन्हें देश विरोधी कहा जाता, पर क्योंकि होसबाले कह रहे हैं तो ठीक है, पर देश में एक राय जरूर है जो बातचीत के पक्ष में है। दोनों देशों की 117 हस्तियों (61 भारत से और 55 पाकिस्तान से) ने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिख कर बातचीत शुरू करने और रिश्ते सुधारने की वकालत की है। लिखने वालों में फारूक अब्दुल्ला और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी शामिल हैं पर जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविन्द्र राणा का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पहले जम्मू कश्मीर में मारे गए बेकसूरों की बात उठानी चाहिए थी। राणा की बात गलत भी नहीं, पर यही होसबाले को बताने की हिम्मत उन्होंने क्यों नहीं उठाई? डा. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने कहा है कि,जब जरूरत हो तो उन्हें खूब हिट करो पर उनके साथ बातचीत के चैनल खुले रखो ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन का फायदा उठाया जा सके, पर क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन का कोई संकेत है? यह भी चर्चा है कि कोलम्बो में दोनों देशों के बीच अनौपचारिक 'ट्रैक टू' वार्ता हो रही है जिसमें पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे भी शामिल हुए थे। सरकारी क्षेत्र उसका प्रतिवाद करते हैं, पर होसबाले के बयान ने चर्चा जरूर शुरू कर दी है।

पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ वार्ता शुरू करने की कई मजबूरियां हैं। आंतरिक स्थिति बेहद खराब है। सिंगापुर के वरिष्ठ राजनयिक बिलहारी कौसिकन ने कहा है कि वह देश बर्बादी के कगार पर है।

बार-बार दूसरे देशों के पास भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ता है, जो बात शहबाज शरीफ ने स्वीकार भी की है, अब तो पीओके की स्थिति भी खराब हो रही है। ईरान के संकट से जो कूटनीतिक बढ़त मिली है वह स्थाई नहीं रहेगी जो बात पाकिस्तान जानता है।

यही कारण है कि शहबाज शरीफ ने पाक से होसबाले के बयान का समर्थन कर दिया, अगर सम्बंध सामान्य हो जाते हैं तो हमें भी लाभ होगा। दोनों देशों के बीच एयरस्पेस खुल जाएगी और पश्चिम की तरफ जाने वाले हमारे विमानों को लम्बा सफर नहीं करना पड़ेगा। ईंधन और समय दोनों की बचत होगी, अगर अटारी-वाघा सीमा से व्यापार शुरू हो जाता है तो पंजाब को विशेष फायदा होगा। भारत और पाकिस्तान बीच तनाव का जो फायदा अमेरिका और चीन उठाते हैं वह भी कम हो जाएगा लेकिन यह बहुत कुछ पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करता है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी घटना में लश्कर-ए- तैयबा के मुखी हाफिज सईद के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की है। वह शख्स पाकिस्तान में है। यह चर्चा है कि पहलगाम का मास्टर माइंड और लश्कर-ए- तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। यह भी सवाल है कि क्या भारत की जनता सम्बंध सामान्य करने के लिए तैयार है? असली बात है कि भारत सरकार क्या चाहती है? सतिन्दर कुमार लाम्बा जो पाकिस्तान में राजदूत भी रह चुके हैं और उस देश के साथ गुप्त वार्ता में बहुत लम्बे समय लगे रहे हैं, ने अपनी किताब इन परसूट ऑफ पीस में लिखा है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता कूटनीतिक नहीं राजनीतिक निर्णय होगा, पर उनका मानना था कि पड़ोस में अस्थिरता के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। उस पड़ोसी से बात न करना जिसकी भारत के प्रति दुश्मनी है, जिसका परमाणु भंडार बढ़ रहा है और जिसकी आंतरिक स्थिति बिगड़ रही है, समझदारी की बात नहीं है-। सतिन्दर कुमार लाम्बा अब रहे नहीं। तब से लेकर बहुत कुछ घट चुका है। भाजपा के नेताओं ने खुद एंटी-पाकिस्तान मूड को बढ़ावा दिया है, पर अब अचानक ठहरे हुए पानी में होसबाले ने पत्थर उछाल दिया है। शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका और रूस में बातचीत होती रही, पर पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर आतंकी घटना युद्ध की कार्रवाई समझी जाएगी, अगर यह सिद्धांत है तो जब तक पाकिस्तान 'आतंकी घटना' नहीं छोड़ देता तब तक उससे बात कैसे होगी? रणनीतिक विशेषज्ञ अजय साहनी ने सवाल किए हैं, क्या वहां जेहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का कोई संकेत है? क्या रावलपिंडी ने प्रायसी युद्ध बंद कर दिया? ऐसे किसी परिवर्तन के कोई संकेत नहीं हैं। उनकी बात सही है। पाकिस्तान कोई संकेत नहीं दे रहा कि वह बंदा बन रहा है। शहबाज शरीफ के बड़े भाई साहिब नवाज शरीफ भी अच्छी अच्छी बातें करते रहे। लाहौर में उन्होंने और वाजपेयी ने खूब जप्फी डाली। वहां अटल जी ने जबान से भरा भाषण भी दिया कि आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, पर पड़ोसी कारगिल कर गया। स्थाई दुश्मनी हमारे हित में नहीं है, पर अच्छे आचरण का प्रमाण तो पड़ोसी ने देना है। जब तक वह ऐसा प्रमाण नहीं देते तब तक बातचीत के लिए बातचीत निरर्थक रहेगी। देश की जनता भी अभी इसके तैयार नहीं है। याद रखिए यह धुरंधर का जमाना है, वीर जारा का नहीं।

मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना' का प्रभावी संचालन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक और भौतिक विकास की रीढ़ माने जाने वाले निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना' का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के निर्माण में दिन-रात पसीना बहाने वाले ये पंजीकृत श्रमिक अक्सर कार्यस्थलों पर अप्रत्याशित जोखिमों और दुर्घटनाओं के साये में काम करते हैं। ऐसे में, यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उस परिवार की आजीविका छिन जाती है। इसी विषम परिस्थिति को भांपते हुए प्रदेश सरकार ने इस अत्यंत कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारा है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में पीड़ित परिवार को तत्काल और पर्याप्त आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सके। यह योजना प्रदेश सरकार की उस संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने और संकट के समय उसे सम्मानजनक जीवन का संबल देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शासन की जन कल्याणकारी नीतियां जब प्रशासन की त्वरित कार्यप्रणाली से जुड़ती है, तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समृद्धि और संतोष स्वतः पहुंच जाता है और शासन का उद्देश्य भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसी कड़ी में जनपद फिरोजाबाद में शासन के निर्देशानुसार समाज के सबसे कर्मठ और श्रम साधक वर्ग निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत आपदा या दुर्घटना के शिकार हुए निर्माण श्रमिकों के पीड़ित परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा एक अत्यंत संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए त्वरित कदम उठाए गए हैं। जनपद फिरोजाबाद में हाल ही में दुर्घटना के शिकार हुए दस निर्माण श्रमिकों के आश्रित परिवारों को आपदा की इस घड़ी में बहुत बड़ा संबल प्रदान किया गया है। प्रशासन की त्वरित तत्परता के चलते इन सभी परिवारों के लिए कुल 52 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गयी है, जिसे सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किये जाने की प्रक्रिया अपनायी गयी है।

> **संक्षेप में कहा जाए तो, उत्तर प्रदेश सरकार की यह दूरदर्शी पहल न केवल श्रमिकों के श्रम का सम्मान करती है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य की उस अवधारणा को पूरी तरह चरितार्थ करती है, जहां हर नागरिक का जीवन और उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित और गरिमापूर्ण है।**

शासन द्वारा इस योजना को बेहद पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के साथ-साथ मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक भी इस सुरक्षा चक्र का सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए यह योजना संकट की घड़ी में एक वास्तविक हमसफर की भूमिका निभा रही है। इस योजना के वित्तीय प्रावधानों के तहत कार्यस्थल पर या दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही, पीड़ित परिवार को 25 हजार रुपये की धनराशि अलग से अंत्येष्टि (अंतिम संस्कार) हेतु प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को कुल 5 लाख 25 हजार रुपये की सम्मानजनक धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कामगार किसी दुर्घटना के चलते आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे उसकी दिव्यांगता की प्रकृति के अनुसार आर्थिक अनुदान दिया जाता है, जिससे वह अपनी चिकित्सा और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हो सके। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्यंत सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान प्रणाली है। स्वीकृत की गयी सम्पूर्ण धनराशि का सीधे उपयोग न करके प्रशासन द्वारा इसे श्रमिक के परिवार के नाम फिक्स्ड डिपाजिट करा दिया जाता है। सरकार द्वारा किया गया यह विशेष प्रावधान इसलिए है ताकि कोई भी बिचौलिया या दलाल सीधे-साधे गरीब परिवारों के पैसों का गबन न कर सके और सहायता का शत-प्रतिशत लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। इस योजना के तहत आश्रित परिवारों को इस फिक्स्ड डिपाजिट की राशि से अगले आठ वर्षों तक प्रतिमाह लगभग 11 हजार रुपये की नियमित मासिक आय प्राप्त होती है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से चल सके। सरकार की इस योजना के पीछे मुख्य मंशा यह है कि भले ही हादसे के कारण परिवार ने अपने महत्वपूर्ण कमाऊ सदस्य को खो दिया हो, परंतु आर्थिक तंगी के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य प्रभावित न हो। प्रशासन द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यमों से जोड़कर इतना सरल और उत्तरदायी बना दिया गया है कि पीड़ित परिवारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और सहायता राशि बिना किसी बाधा के सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित हो जाती है। इस समयबद्ध आर्थिक मदद से न केवल आश्रितों को मानसिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और परिवार के जीवन की निरंतरता भी भंग नहीं होती। जनपद फिरोजाबाद में शासन के मानवीय दृष्टिकोण से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों के परिजनों में सरिता पत्नी स्व0 राकेश कुमार, गुड्डी देवी पत्नी स्व0 अवैद्य राम, दानवती पत्नी स्व0 राजेश, ओमवती पत्नी स्व0 प्रमोद कुमार, विनीता देवी पत्नी स्व0 कर्मवीर सिंह, शिखा पत्नी स्व0 सत्यप्रकाश, हेमलता पत्नी स्व0 सुभाष चन्द, गुड्डी देवी पत्नी स्व0 ज्ञान सिंह, और गीता देवी पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद शामिल हैं। इसके साथ ही, शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 रवीकांत जो कि मनरेगा जॉब कार्ड धारक श्रमिक हैं, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत पूर्ण लाभ प्रदान कर सुरक्षित किया गया है। इन सभी परिवारों को त्वरित गति से लाभ मिलने से इन्हें कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन का स्पष्ट मत है कि मानवीय दृष्टि से सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ त्वरित गति से पात्रों को प्रदान किया जाता रहेगा, जिससे उनके परिवार को कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना न करना पड़े और उनके बच्चे और परिवार की जिंदगी सुचारू रूप से संचालित होती रहे। संक्षेप में कहा जाए तो, उत्तर प्रदेश सरकार की यह दूरदर्शी पहल न केवल श्रमिकों के श्रम का सम्मान करती है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य की उस अवधारणा को पूरी तरह चरितार्थ करती है, जहां हर नागरिक का जीवन और उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित और गरिमापूर्ण है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2018/XXXXX)

बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदला, ऊमस से मिली राहत

हल्की बारिश होने से रोपाई तेज, शहर में कीचड़युक्त रास्तों से बढ़ी दुश्वारियां

महराजगंज।

मौसम का मिजाज बदलने के कारण ऊमस से थोड़ी राहत मिली। बृहस्पतिवार को सुबह से ही हल्की बूंदाबादी होती रही। जिले में कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इससे रोपाई में तेजी आ गई। वहीं दूसरी शहर में सड़कें कीचड़युक्त होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले चार दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना है। बृहस्पतिवार सुबह सात बजे हल्की बूंदाबांदी हुई। कुछ देर बाद मौसम सामान्य हो गया। इसके बाद बदली छा गई। दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदलने से कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इससे किसानों से राहत महसूस की। मोहनापुर के किसान राजेंद्र यादव कहते हैं कि इन दिनों बारिश की बेहद जरूरत है। जिले में अभी तमाम स्थानों पर रोपाई नहीं हुई है। बारिश होने के कारण पंपिंगसेट से सिंचाई करने में समय कम लगेगा। क्योंकि खेत में नमी है। मौसम कुछ दिनों तक इसी तरह से बना रहा तो समस्या नहीं होगी। चेहरी के गोविंद मणि ने बताया कि एक सप्ताह पहले रोपाई की गई थी। अब सिंचाई की जरूरत महसूस हो रही थी। हल्की बारिश होने से खेतों में नमी लौट आई है। इससे रोपाई को फायदा हुआ है। वहीं दूसरी ओर से महराजगंज नगर क्षेत्र की बात करें तो गांधी नगर मोहल्ले में बदहाल सड़क कीचड़युक्त हो गई है। पहले से खराब हुई सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। घरों से निकला गंदा पानी सड़क पर होने से समस्या हो रही है। सड़क पर कुछ स्थानों पर मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर दिया गया है। ऐसे में बारिश होने से कीचड़ के कारण फिसलन बढ़ गई है। गांधी नगर के राजेंद्र बाइक से जाने के दौरान गिरकर घायल हो गए। उन्होंने बताया कि गांधी नगर में घरों के सामने कुछ जगहों पर नाली बंद कर दी गई है। कुछ स्थानों पर सड़क पर मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर लिया गया है। जब कभी हल्की बारिश होती है तो आना जाना बेहद खतरनाक हो जाता है। शहर में ही चिउरहा रोड पर नाला निर्माण के लिए खोदाई करके छोड़ दिया गया है।

दुकानदारों की आमदनी प्रभावित हो गई है। रास्ता नहीं होने के कारण ग्राहक दुकान पर नहीं पहुंच रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडेय ने बताया की आने वाले चार दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार होने के साथ ही तेज हवा चल सकती है।

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक

भटनी पुलिस ने बांटे पंपलेट, नए कानून, हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

भटनी देवरिया।

थाना भटनी पुलिस द्वारा बृहस्पतिवार को मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, भारत सरकार के नए कानूनों तथा महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं और जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए। पुलिस टीम ने महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1090 एवं 1930 की उपयोगिता बताते हुए आवश्यकता पड़ने पर इनके प्रयोग के लिए प्रेरित किया।

साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष योजना, फैमिली काउंसलिंग सहित महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान साइबर अपराध एवं बाल विवाह जैसे अपराधों के प्रति भी महिलाओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर उपनिरीक्षक सत्य प्रकाश दुबे, कांस्टेबल अरविंद यादव तथा महिला कांस्टेबल बेबी यादव मौजूद रहीं।

शौच के लिए गए युवक पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सौराहा खुर्द-दुबरहा गांव में गुरुवार शाम शौच के लिए खेत में गए एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, सौराहा खुर्द-दुबरहा गांव निवासी युगल किशोर, पुत्र गुलाब, गांव के दक्षिण स्थित खेत में शौच के लिए गए थे। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल युगल किशोर घटनास्थल पर ही लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की सूचना परिजनों को दी।

पाइपलाइन लीकेज से हतवा का मुख्य मार्ग बदहाल, राहगीरों के लिए बना खतरा

भटनी देवरिया।

नगर पंचायत के हतवा गांव का मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है। शिव मंदिर से आदर्श चौराहा तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क लगभग आठ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। कई जगह पाइपलाइन में लगातार लीकेज होने से सड़क टूटती जा रही है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह मार्ग गांव का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां दिनभर ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल और अन्य छोटे वाहनों का आवागमन रहता है। सड़क के बीच बने गहरे गड्ढों और लगातार हो रहे जलभराव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई ई-रिक्शा पलट चुके हैं तथा बाइक और साइकिल सवार गिरकर घायल हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पाइपलाइन लीकेज को तीन से चार बार ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। हर बार कुछ दिनों बाद फिर से पाइपलाइन रिसने लगती है, जिससे सड़क और अधिक क्षतिग्रस्त होती जा रही है।

शिव मंदिर से आदर्श चौराहा तक लगभग आठ स्थानों पर रिसाव, कई बार मरम्मत के बाद भी नहीं रुकी समस्या

चेयरमैन भटनी ने जलनिगम जेई व एक्सईएन को 20 दिन में ठीक करने की दी हिदायत

पाइप लाइन लीकेज मामले पर नगर पंचायत भटनी चेयरमैन विजय कुमार गुप्त उर्फ मुन्ना ने जलनिगम के जेई व एक्सईएन को इस लीकेज को ठीक करने के लिए 20 दिन में सही करने की हिदायत दी। चेयरमैन ने कहा कि हम नगर की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

शासन को भेजा गया कुलकुला देवी मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 4.99 करोड़ का प्रस्ताव

कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की पहल पर कसया तहसील स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के मां कुलकुला देवी एवं भगवान शिव मंदिर, कुड़वा दिलीप नगर के पर्यटन विकास के लिए 4.99 करोड़ (499.54 लाख) की विस्तृत परियोजना (डीपीआर) तैयार कर शासन को भेजी गई है। पर्यटन विभाग के माध्यम से तैयार इस प्रस्ताव का उद्देश्य मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर इसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। कसया तहसील मुख्यालय से लगभग सात किलोमीटर दूर हिरण्यावती नदी के तट पर स्थित कुलकुला देवी मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहां पूजा-अर्चना की थी। नववर्ष, रामनवमी और चैत्र मास के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में एक माह तक चलने वाला विशाल मेला भी आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर पर्यटन विभाग की कार्यदायी संस्था सी एंड डी एस, यूनिट-42 गोरखपुर द्वारा इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट के माध्यम से परियोजना का विस्तृत आगणन तैयार कराया गया। जिलाधिकारी ने 8 जुलाई 2026 को महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजते हुए परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित योजना में दो भव्य प्रवेश द्वार, कलश चौराहा, त्रिशूल पेडेस्टल, जी+1 मल्टीपर्पस हॉल, आकर्षक पाथवे, साइनेज, महिला, पुरुष एवं दिव्यांगजन के लिए आधुनिक शौचालय, ब्रेस्ट फीडिंग कक्ष, गज़ीबो, इंटरप्रिटेशन वॉल, पेयजल व्यवस्था, पार्क, समतलीकरण, दुकानें, स्ट्रीट एवं हाईमास्ट लाइट, सोलर लाइट, बोलार्ड लाइट तथा सीसी रोड सहित विभिन्न आधारभूत एवं पर्यटन सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन से कुलकुला देवी मंदिर का धार्मिक और पर्यटन महत्व और अधिक बढ़ेगा। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा कुशीनगर के पर्यटन विकास को नई दिशा मिलेगी।

जंगल नाहरछपरा में सामाजिक सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

पडरौना, कुशीनगर। विकास खंड पडरौना के जंगल नाहरछपरा बड़ा सेमरहना स्थित काली स्थान पर श्रमिक सुविधा केंद्र, एक्शनएड एसोसिएशन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महिला कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में असंगठित श्रमिकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा आमजन को सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता रामवृक्ष गिरि ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा श्रमिक सुविधा केंद्र की सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी पंकज खरवार ने प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं सेवाओं की जानकारी दी। सुधीर यादव ने जनसंख्या नियंत्रण तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जागरूक किया। महिला कल्याण विभाग के नलिन सिंह ने महिला एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जबकि एक्शनएड एसोसिएशन के दिनेश प्रसाद ने श्रम विभाग की योजनाओं से अवगत कराया। राजू प्रसाद ने नशा मुक्ति और श्रमिकों को अपने अधिकारों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। शिविर में रविंदर प्रसाद, कमली, रम्भा, किरण, पन्नेलाल, छोटाई, सिकंदर, गुंजा, तूफानी प्रसाद, कुसुम, रामनरेश प्रसाद, सत्तन प्रसाद, प्रीति सिंह, रामअशीष कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना रहा।

देवरिया स्टेशन पर आरपीएफ की मुस्तैदी, लावारिस बैगों से 43 हजार की अंग्रेजी शराब बरामद

देवरिया।

ट्रेनों और रेलवे परिसरों के जरिए होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अपराध आसूचना शाखा (सीआईबी) ने संयुक्त रूप से एक बड़ी सफलता अर्जित की है। गुरुवार दोपहर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर चलाए गए सघन निगरानी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने प्लेटफार्म संख्या दो-तीन पर लावारिस हालत में रखी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। यह कार्रवाई आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत की गई, जिससे स्टेशन परिसर में सक्रिय संदिग्ध तत्वों में हड़कंप मच गया। स्टेशन पर आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के दौरान सीआईबी भटनी के उप निरीक्षक चंद्रसेन सिंह, सहायक उप निरीक्षक अवनीश राय, सीआईबी फील्ड मुख्यालय गोरखपुर के अबू फरहान गफ्फार और आरपीएफ पोस्ट देवरिया सदर के उप निरीक्षक रामशंकर सिंह, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र यादव व कांस्टेबल दीनानाथ यादव की संयुक्त टीम प्लेटफार्म संख्या दो-तीन के पूर्वी फुटओवर ब्रिज के पास मौजूद थी।

इसी दौरान टीम की नजर वहां लावारिस अवस्था में रखे तीन पिट्ठू बैग, तीन बड़े झोलों और दो लेडीज हैंड बैग पर पड़ी।

काफी देर तक किसी भी यात्री द्वारा उन बैगों पर दावा न किए जाने के बाद सुरक्षा टीम ने सतर्कता बरतते हुए दोपहर करीब 02:20 बजे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया।?खोले जाने पर बैगों के भीतर से अवैध रूप से तस्करी की जा रही अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामदगी के ब्यौरे के अनुसार, बैगों से रॉयल स्टैग व्हिस्की की 750 एमएल वाली 18 बोतलें (कीमत 690 रुपये प्रति बोतल) और ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की के 180 एमएल वाले 236 टेट्रा पैक (कीमत 130 रुपये प्रति पैक) बरामद किए गए। जब्त की गई कुल 55.98 लीटर अंग्रेजी शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 43,100 रुपये आंकी गई है। बरामद माल को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए देवरिया सदर आरपीएफ पोस्ट को सुपुर्द कर दिया गया है। इस तत्परता से साफ है कि रेल प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और अवैध धंधों पर अंकुश लगाने को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है।

रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हमारा अभियान निरंतर जारी है। सीआईबी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्लेटफार्म से लावारिस हालत में करीब 43 हजार रुपये मूल्य की अंग्रेजी शराब जब्त की है। संभावना है कि तस्कर पुलिस की सघन चेकिंग को देखकर माल छोड़कर भाग निकले। इस संबंध में अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

फुटओवर ब्रिज के पास मिले तीन पिट्ठू बैग, तीन झोले और दो लेडीज हैंड बैग; 55.98 लीटर तस्करी की खेप जब्त कर जांच शुरू, तस्करों की तलाश तेज

गुरुग्राम में दीपक नांदल गैंग के चार शूटर ढेर, तीन पुलिसकर्मी भी घायल

मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत मेदांता अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

गुरुग्राम । गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा की टीमों ने बृहस्पतिवार देर रात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के चार शूटरों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। वहीं, गोली लगने से घायल हुए पांचवें शूटर को अस्पताल ले जाया गया है। एनकाउंटर में बदमाशों की ओर से चलाई गोली लगने से तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास कौशिक ने एनकाउंटर में चार 4 शूटरों की मौत और 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार, सुशांत लोक में ए ब्लॉक के मकान के बाहर बृहस्पतिवार देर रात लगभग 11 बजे पुलिस और बदमाशों का आमना-सामना हुआ।

यह मकान झज्जर के मूल निवासी प्रॉपर्टी डीलर विशाल बेरी का बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दीपक नांदल गैंग के पांच शूटर स्कॉर्पियो में सवार होकर रंगदारी के इरादे से यहां पहुंचे थे। इसकी सूचना अपराध शाखा की टीमों को पहले से लग गई। पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। अपराध शाखा सेक्टर-31 इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद यादव और सेक्टर-40 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जैसे ही काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम को देखा तो गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। मौके पर 20 से अधिक गोलियां चलीं। इस दौरान 4 शूटरों को पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि पांचवां बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। एनकाउंटर में एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीनों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्हई गांव में 2 मई की देर रात सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर सौरभ के घर पर गोली चलाने के मामले में भी गैंगस्टर दीपक नांदल के चार गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों की पहचान रोहतक के बखेता गांव निवासी अशोक उर्फ पहलवान, चौंडी गांव निवासी मनोज कुमार, सोनीपत के कथुरा गांव निवासी सुमित और गांव गढ़ शाहजहांपुर निवासी विक्की के रूप में हुई थी। आरोपियों ने गैंगस्टर दीपक के कहने पर ही रैकी और हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। मैनेजर के घर बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली चलाई थी। वारदात के दौरान मैनेजर को मिले सुरक्षाकर्मी सिपाही कुलबीर के हाथ और पैर पर गोली लगी थी। सिपाही की शिकायत पर ही सेक्टर-40 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

मोदी ने मेलबर्न में 30 हजार भारतीयों को संबोधित किया

मेलबर्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार को मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मेगा शो में 30 हजार भारतीय शामिल हुए। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का एक बार फिर जिक्र किया है। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हुए धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके पड़ोसियों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। आतंकी कैंप पर इस कड़े प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता, भारत कह रहा है ये मोर, ये मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भारतीय ऐसे ही है जैसे दूध में चीनी मिल जाती है और उसे और भी मीठा कर देती है।

वैसे ही, हम भारतीय दुनिया भर में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते है। घर में दूध तो ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है... उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में आजकल भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। हमारी Gen Z इसे आगे बढ़ा रही है और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी, मैंने सुना है कि आपके वीकेंड भी आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, तो कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चे द्वारा भांगड़ा, कहीं भरतनाट्यम की प्रस्तुति या कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। वेनेजुएला में भूकंप के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन अमिस्ताद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा आपदा में मदद करता है। हम जब मदद करते है तो नागरिकों के पासपोर्ट नहीं देखते। दुनिया आज भारत पर भरोसा करती है। पीएम मोदी ने तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप के दौरान भी भारत की तरफ से भेजी गई मदद का जिक्र किया। उन्होंने खेल के क्षेत्र में दिए गए योगदान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि शिक्षा, हुनर और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते गहरे और मजबूत हो रहे हैं। आज हजारों भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं।

टीएमसी से बगावत का बीजेपी ने दिया इनाम

सुष्मिता-सुखेंदु शेखर समेत तीन नेताओं को राज्यसभा टिकट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तीन पूर्व राज्यसभा सांसद को बड़ा इनाम मिला है। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बड़ाईक को भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तीनों नेताओं ने गुरुवार को ही भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने कुछ ही घंटे बाद उन्हें टिकट देकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया। यह उपचुनाव उन तीन सीटों पर हो रहा है जो इन नेताओं के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर 24 जुलाई को मतदान कराने का एलान किया है। दूसरी ओर भाजपा ने गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए मंजलपुर से सतीशभाई गोविंदभाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है।

हम सिर्फ विकास चाहते है - प्रकाश चिक बड़ाईक

राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रकाश चिक बड़ाईक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 49 वर्षों में, 34 साल के वाम शासन और 15 साल के तृणमूल शासन के दौरान कई विकास कार्य पूरे नहीं हो सके। राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी रही। पांच साल तक 100 दिन रोजगार योजना का पैसा रुका रहा और गरीबों के लिए कई योजनाएं प्रभावित हुईं। बड़ाईक ने आगे कहा कि इस बजट में उत्तर बंगाल में एम्स, कई मेडिकल कॉलेज, सिलीगुड़ी से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन और हासीमारा में एयरपोर्ट का प्रस्ताव है। हम सिर्फ विकास चाहते है। अगर पहले ही राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल होता, तो ये समस्याएं पैदा नहीं होतीं।

फिर से संवरेगी पुरानी दिल्ली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम को सौंपी जिम्मेदारी

दिल्ली । एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विरासत को फिर से संवारने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इस निगम के जरिए पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए उसे आधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस करने की एक व्यापक और गंभीर पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास मंत्री और निगम के उपाध्यक्ष आशीष सूद, प्रबंध निदेशक संदीप कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, नागरिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया कि ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाजार का डिजाइन उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट रूप से दिखाए। उन्होंने इलाके में रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए आधुनिक और काम के लायक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाने के भी निर्देश दिए। ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने निर्देश दिया कि चांदनी चौक की तरफ से भी एक मुख्य प्रवेश और निकास द्वार बनाया जाए, ताकि यह ऐतिहासिक इमारत एक प्रमुख विरासत और पर्यटन स्थल के रूप में उभर सके। बैठक में विरासत संरक्षण और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के हितों की रक्षा करने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक बाजार इलाके के विकास के साथ-साथ विकसित हुआ है और इसकी पुरानी शान को वापस लाने के लिए इसके बाजारों, व्यापारियों और दुकानदारों के हितों को सबसे आगे रखना होगा। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक के पुनर्विकास में इसके बाजारों, पर्यटकों, खरीदारों और स्थानीय निवासियों, सभी के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को जानकारी, मार्गदर्शन और तुरंत मदद देने के लिए बाजार में एक खास कंट्रोल रूम बनाया जाए।

फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, यूसीसी के लिए बनी 7 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी

पुणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। इस कमेटी में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र से दो लोग शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में यह घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरवी चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री गिरीश प्रभुणे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल मुख्य सदस्य होंगे। सीएम फडणवीस ने कहा कि सात सदस्यों वाली यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेगी और अगले छह महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट फाइनल करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागपुर में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करने और उसे पास कराने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सभी जरूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी, ताकि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इससे पहले पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो भारत में पर्सनल लॉ और कानूनी एकरूपता पर चल रही बहस में एक अहम घटनाक्रम है। इस मुद्दे पर बात करते हुए, फडणवीस ने कहा कि सरकार इस कानून को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार संविधान में शामिल राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से समर्थन पाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि एक समान नागरिक ढांचा शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समानता और एकरूपता के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूरे देश में इस पर चर्चा तेज हो गई है। आजादी के बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना, और उम्मीद है कि महाराष्ट्र अपना ड्राफ्ट तैयार करते समय उत्तराखंड के अनुभव का बारीकी से अध्ययन करेगा।

ममता को कोर्ट से राहत- पार्टी के तीनों खातों से पैसा निकाल सकेगी टीएमसी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को दो बड़े घटनाक्रम सामने आए। एक ओर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गुट वाले तृणमूल कांग्रेस को पार्टी के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया, वहीं दूसरी ओर अदालत ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास पर अदालत परिसर में कथित अंडे फेंकने की घटना पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों की सार्वजनिक बेइज्जती और उन पर अंडे फेंकने जैसी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने रिटायर्ड जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। अदालत ने तय किया कि उनकी निगरानी में ही टीएमसी अपने फ्रीज किए गए बैंक खातों का सीमित इस्तेमाल कर सकेगी। बिल्कुल नहीं। अदालत ने साफ कर दिया कि खातों से सिर्फ पार्टी के रोजमर्रा के संचालन और कानूनी मामलों से जुड़े खर्च ही किए जा सकेंगे।

ईरान बोला- होर्मुज में दखल दिया तो करारा जवाब देंगे

तेल अवीव । ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में दखल दिया तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक, IRGC ने कहा कि अमेरिका ने हमला जारी रखा तो होर्मुज सामान्य नहीं हो पाएगा और कई देशों को आर्थिक नुकसान होगा। दूसरी ओर, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस से जुड़े एक रणनीतिक रेलवे पुल पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। अमेरिका ने पिछले 2 दिनों में ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल भंडार, सैन्य स्पीड बोट और होर्मुज स्ट्रेट के पास तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

खड़गे का मोदी सरकार पर हमला- गलवान के बाद चीन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा

मेलबर्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार को मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मेगा शो में 30 हजार भारतीय शामिल हुए। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का एक बार फिर जिक्र किया है। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हुए धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी।

पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनी- पीएम

भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके पड़ोसियों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। आतंकी कैंप पर इस कड़े प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता, भारत कह रहा है ये मोर, ये मोर।

भारतीय ऐसे ही है जैसे दूध में चीनी मिल जाती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भारतीय ऐसे ही है जैसे दूध में चीनी मिल जाती है और उसे और भी मीठा कर देती है। वैसे ही, हम भारतीय दुनिया भर में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते है। घर में दूध तो ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है... उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में आजकल भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। हमारी Gen Z इसे आगे बढ़ा रही है और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी, मैंने सुना है कि आपके वीकेंड भी आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण

की कथा, तो कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चे द्वारा भांगड़ा, कहीं भरतनाट्यम की प्रस्तुति या कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है।

हम जब मदद करते हैं तो नागरिकों के पासपोर्ट नहीं देखते

वेनेजुएला में भूकंप के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन अमिस्ताद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा आपदा में मदद करता है। हम जब मदद करते है तो नागरिकों के पासपोर्ट नहीं देखते। दुनिया आज भारत पर भरोसा करती है। पीएम मोदी ने तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप के दौरान भी भारत की तरफ से भेजी गई मदद का जिक्र किया। उन्होंने खेल के क्षेत्र में दिए गए योगदान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि शिक्षा, हुनर और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते गहरे और मजबूत हो रहे है। आज हजारों भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे है और अब ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है। डीकिन और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटीज के कैंपस शुरू हो चुके है और दूसरी ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और यह सिर्फ नए कैंपस खोलने की बात नहीं है, यह दुनिया को कुशल और इनोवेटिव टैलेंट देने वाले ग्लोबल लीडर तैयार करने का एक अभियान भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे को याद करते हुए कहा कि उस समय करीब 28 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। उन्होंने कहा, उस दौरान मैंने कहा था कि अगली बार भारत के प्रधानमंत्री के आने के लिए लोगों को 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह उनकी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा है और यह एक तरह से 'हैट्रिक' है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव दर्शाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध कितनी तेजी से मजबूत हुए है।

सक्षम भारत की वेबसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

350 साल पुरानी दिल्ली को चमकाने के लिए रेखा सरकार का मास्टर प्लान, जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक बदलेगी सूरत

नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआरडीसी) का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को उसके मूल स्वरूप के साथ सुरक्षित रखते हुए व्यापक पुनर्विकास का काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का डिजाइन ऐसा तैयार किया जाए, जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा बरकरार रहे। उन्होंने प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए आधुनिक सार्वजनिक शौचालय विकसित करने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के भी निर्देश दिए।

सरकार का उद्देश्य इस ऐतिहासिक इमारत को प्रमुख विरासत एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि पुनर्विकास के दौरान स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के हितों की अनदेखी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक का विकास बाजार, व्यापारियों, पर्यटकों, खरीदारों और स्थानीय निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए चांदनी चौक में कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और त्वरित सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर और उसके पीछे के क्षेत्र के समग्र विकास का विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जामा मस्जिद क्षेत्र तथा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के सुंदरीकरण और पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने का भी फैसला लिया गया।